THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (d) According to the current policy of the Government, in cases of nationalisation of industrial units taken over under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the entire pre-take over dues, including interest, of banks and financial institutions are required to be fully protected by the Government nationalising the unit. The policy relating to protection of dues, including the pre-takeover dues, is being reviewed. A delegation of Members of the West Bengal Legislative Assembly met the Union Finance Minister recently and has submitted a Memorandum which, *inter-alia*, seeks the removal of the condition of protecting the pre-take over dues.

Hushing up of Currency Racket

1867. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report which appeared in the *Blitz* on the 18th May, 1985 to the effect that inquiry into the sensational currency racket involving three persons, viz. Shri Mrugesh Jaikrishna, his wife Paru and Shri Chandrakant Sivabhai Amin has been hushed up; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) The Government have seen the news item referred to in the question. The news item, however, does nowhere state that the inquiry in this case has been hushed up. The foreign currency of Rs. 46.63 lakhs recovered on 19th March, 1985 has already been seized. S/Shri Mrugesh Jaikrishna, Asutosh Prafulchandra Nanavathy and Chandrakant Sivabhai Amin who were arrested in connection with smuggling of foreign currency were subsequently detained under the Cofeposa Act. Further investigations are in progress and appropriate action as warranted under the law would be taken against all the persons involved.

1868. [*Transferred to the 22nd August, 1985.*]

Export of Automobile tyres and tubes

1869. SHRIMATI MONIKA DAS: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what was the quantum of automobile tyres and tubes exported during the year 1984-85; and

(b) what is the quantum of automobile tyres and tubes likely to be exported during the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): (a) The total value of automobile tyres and tubes exported during the year 1984-85 is estimated at Rs. 495.0 million.

(b) The value of export will depend upon the demand in the international market.

चीनी-विक्रेताओं द्वारा काले धन का संचय

1870. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :
श्री कैलाश पति मिश्र :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किये गय अध्ययन के अनुसार चीनी उद्योग में जो काला धन संचित होता है वह चीनी के वार्षिक उत्पादन के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर है और जो 1976-77 में लगभग 249 करोड़ रुपया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, चीनी विक्रेताओं, वितरकों और उत्पादकों द्वारा काले-धन की कितनी राशि संचित की गई तथा उनकी कार्य-प्रणाली क्या थी; और

(ग) सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चीनी उद्योग में अवैध आय की उत्पत्ति के बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किए जा रहे विस्तृत अध्ययन का इन्तजार किया जा रहा है । संस्थान की रिपोर्ट में किए गए प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया, सार्वजनिक बहस के समाप्त होने और सुझावों के मिलने के बाद ही दीर्घकालीन वित्तीय नीति में अभिव्यक्त की जायेगी ।

राज्यों को ओवर-ड्राफ्ट भुगतान

1871. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में मार्च, अप्रैल, 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक और महालेखाकार की भूलों के कारण कुछ दूसरे राज्यों के भुगतानों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) रिजर्व बैंक और महालेखाकार की इस भूल के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी भूले नहीं हों, क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक राज्य विशेष को स्वीकृत एक बड़ी धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गलती से किसी दूसरे राज्य के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी थी कि यदि वे निरन्तर सात कार्य दिवसों से अधिक के लिए 28-1-85 के अपने ओवर-ड्राफ्ट की सीमाओं से अधिक ओवर-ड्राफ्ट में रहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उनके भुगतानों को बंद कर देगा । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ने क्रमशः फरवरी और अप्रैल; 1985 में इन स्तरों को पार कर लिया था और प्रत्येक के भुगतान एक दिन के लिए रोक दिए गए ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने और किसी राज्य का भुगतान बंद नहीं किया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए बैंक ऋण

1872. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 जून, 1985 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि लगभग 3 करोड़ मीटरी टन खाद्यानों के भण्डारण के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपए के बैंक ऋण की धनराशि अंतर्ग्रस्त है जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां ।

गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों के